रोपन साहू और अन्य

बनाम

आनंद कुमार शर्मा और अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 615)

22 जनवरी, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965 - आर. 34 (1) परंतुक-का अनुदान आई. एम. एफ. एल. लाइसेंस-नियमों में ढील देकर-चुनौती-उच्च अदालत ने इस आधार पर लाइसेंस देने को रद्द कर दिया कि नियमों में ढील देने का कोई आदेश नहीं था-अपील पर, उस आदेश का अनुरोध करें लाइसेंस देना आर के परंतुक के अनुरूप था। 34 (1) –आयोजित किया गयाः फाइल में नोट-शीट से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राधिकरण को दूरी पर प्रतिबंधों के बारे में पता था पसंदीदा स्थान और विश्राम के लिए अनुशंसित-गैर नियम का उल्लेख करना किसी आदेश को पारित न करने के समान नहीं है-इस प्रकार लाइसेंस देने का आदेश अनुरूप था।आर के प्रावधान के साथ। 34 (1) - इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नियमों में ढील देने का कोई आदेश नहीं था।

आई. एम. एफ. एल. 'ऑन' दुकान के संबंध में लाइसेंस दिया गया था। 2013 के C.A.No.615 में अपीलार्थियों के पक्ष में। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अनुच्छेद के तहत रिट याचिका दायर की। 226 में से संविधान, लाइसेंस के अनुदान को चुनौती देता है। अदालत ने रिट याचिका पर विचार किया और अनुदान को रद्द कर दिया अनन्य विशेषाधिकार और अनुज्ञप्ति, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि न्यूनतम प्रतिबंधों में ढील देने का कोई आदेश नहीं था आर के खंड (डी) और (ई) में उल्लिखित दूरी। 34 प्रस्तावित दुकानों से संबंधित उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965 उक्त नियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। इसलिए प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य द्वारा वर्तमान अपील। द.राज्य ने इस बात को उजागर करने के लिए फाइल में नोट-शीट का उल्लेख किया है कि आदेश आर के परंतुक के अनुरूप पारित किया गया था। 34 (1) नियमों से।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कारण कि उड़ीसा को शिथिल करने का कोई आदेश नहीं था विशेष अनुदान के आदेश से पहले उत्पाद शुल्क नियम, 1965 विशेषाधिकार पारित किया गया था, सही नहीं है। गहन जांच पर पूरे नोट-शीट से यह स्पष्ट है कि आयुक्त-सह-सचिव ने स्वीकार किया था कलेक्टर और आबकारी विभाग की सिफारिशें संयुक्त सचिव ने विचार के लिए फिर से नियुक्त किया था और आबकारी और

पर्यटन मंत्री द्वारा अनुमोदन। द.मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद फाइल चली गई थी। संचार के लिए वापस। मंत्री के हस्ताक्षर करने के बाद द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर फाइल आयुक्त-सह-सचिव जिसकी स्थापना की गई थी संयुक्त सचिव की सिफारिशें जिन्होंने कलेक्टर की सिफारिशों से सहमत और आबकारी आयुक्त, संचार थे संयुक्त सचिव द्वारा बनाया गया। नोट-शीट स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तथ्यों के लिए मन के अनुप्रयोग का संकेत दिया जो प्रस्तावित स्थल और मंत्री द्वारा अनुमोदन। [पैरा 18] [1141 - बी-एफ]

टाफकॉन प्रोजेक्ट्स (आई) (पी) लिमिटेड v. भारत संघ और अन्य। (2004) 13 एस. सी. सी. 788-पर निर्भर था।

नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य आकाशवाणी 2011 एससी3199: 2011 (12) एससीआर 84; यू. पी. और अन्य राज्य। वी. प्रधान संघ क्षेत्र समिति और अन्य। ए. आई. आर. 1995 एससी 1512 : 1995 (2) एससीआर 1015; शमशेर सिंह बनाम। की स्थिति पंजाब और अन्र। ए. आई. आर 1974 एस. सी. 2192: 1975 (1) एससीआर 814; सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन और ए. एन. आर. वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण और ओआरएस। (2009) 1 एससीसी 180: 2008 (14) एससीआर 598; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। एम. आर. मंडल और अन्र. ए. आई.

आर. 2001 एससी 3471 : 2001 (2) पूरक। एस. सी. आर. 531-संदर्भित।

2. नोट-शीट का संचयी प्रभाव एक है यह दिखाने के लिए लंबा रास्ता है कि हर प्राधिकरण को पता था दूरी और खंडों में छूट के लिए अनुशंसित (डी) और (ई) नियम 34 के उप-नियम (1) और संबंधित मंत्री ने भी इसका समर्थन किया था। नियम या उप-नियम का उल्लेख न करना पारित न होने के समान नहीं है। एक आदेश। प्रमुख परीक्षण का अनुप्रयोग होना चाहिए प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दें। आदेश का दूसरा भाग, यदि उचित रूप से सराहना की जाती है, तो यह बताता है कि कोई कारण नहीं है अभिनिर्धारित किया गया। नियम 34 (1) के प्रावधान में एक अभिधारणा दी गई है। कि खंड (घ) और (ङ) के तहत उल्लिखित दूरी राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी जा सकती है परिस्थितियाँ। द्वारा की गई सिफारिशें कलेक्टर उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है, अर्थात्, वहाँ होटल परिसर के भीतर शराब पीने की मांग है; कि अवैध शराब के मामले दर्ज किए गए हैं निकटवर्ती क्षेत्र; और यह कि प्रस्ताव हित में है सरकारी राजस्व से। उक्त सिफारिशें उच्च अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वे गठन करते हैं

विशेष परिस्थितियाँ। [पैरा 24] [1144-एच; 1145-ए-डी]

मामला कानून संदर्भः उस पर भरोसा करें

(2004) 13 एस. सी. सी. 788 संदर्भित किया गया है पैरा 18

2011 (12) एससीआर 84 संदर्भित किया गया है पैरा 20

1995 (2) एससीआर 1015 संदर्भित किया गया है पैरा 21

1975 (1) एससीआर 814 संदर्भित किया गया है पैरा 21

2008 (14) एससीआर 598 संदर्भित किया गया है पैरा 22

2001 (2) पूरक। एस. सी. आर. 531 संदर्भित किया गया है पैरा 23

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 615/2013

उड़ीसा उच्च न्यायालय , कटक द्वारा डब्ल्यू. पी (ग) सं. 3913/2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 16.09.2009 से उत्पन्न।

के साथ

सिविल अपील संख्या 616/2013

भास्कर पी. गुप्ता, शिबाशीष मिश्रा, अरुण पात्र, अभिनंदन नंदा, कीर्ति रेणु मिश्रा, अपूर्णा उपमान्यु, जी। रामकृष्ण प्रसाद, बी. सुयोधन, मोहम्मद। वसी खान, फिल्ज़ा दिखाई देने वाली पार्टियों के लिए मूनिस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, जे. 1. विशेष याचिकाओं पर अनुमति दी गई.

2. दिनांकित आदेश की कानूनी स्वीकार्यता पर सवाल उठाना 2009 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3913 में कटक में उड़ीसा जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रथम द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार किया यहाँ प्रत्यर्थी और अनन्य विशेषाधिकार के अनुदान को रद्द कर दिया कुमार, प्रत्यर्थी सं। 5 और रिट याचिका में 6, दुखी व्यक्तियों द्वारा वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

3. अनावश्यक विवरणों से कटे हुए तथ्य जो हैं यह बताना आवश्यक है कि मुकेश कुमार, प्रतिवादी नं. 6 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था वार्ड संख्या 16 में आई. एम. एफ. एल. "बंद" दुकान खोलने के लिए लाइसेंस का अनुदान, 28.1.2008 पर वर्ष 2007-08 के लिए बारगढ़ शहर। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तावित स्थल उप-नियम का उल्लंघन था 1 (ग) उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965 के नियम 34 (संक्षेप में "नियम") के अनुसार, उक्त प्रतिवादी ने आवेदन वापस लेने का फैसला किया। व्यक्तिगत कारणों का संकेत देकर उपरोक्त वर्ष के लिए। अगले वित्तीय वर्ष का सम्मान उन्होंने फिर से प्रस्तुत किया उसी स्थान पर लाइसेंस देने के लिए आवेदन। कलेक्टर, बारगढ़ ने आपत्तियाँ आमंत्रित कीं और उसी के अनुसार रिट याचिकाकर्ता ने 18.10.2008 पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आबकारी निरीक्षक ने 2.2.2009 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की स्नान घाट, विष्णु मंदिर, बस स्टैंड और प्रतिबंधित दूरी के भीतर पेट्रोल पंप, लेकिन प्रतिबंधों में ढील देने की

सिफारिश की गई। कलेक्टर, बरगढ़, शेष भाग के लिए दुकान खोलने की सिफारिश की गई वर्ष 2008-09 प्रतिबंधों में छूट और आबकारी आयुक्त ने भी सरकार को इस पर सिफारिश की 19.2.2009 प्रतिबंधों में ढील देकर मंजूरी के लिए। जिस तरह से तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा कि राज्य सरकार इस आधार पर सिफारिशों के तहत छूट की शक्ति का आह्वान किया गया नियमों के नियम 34 और उक्त के पक्ष में लाइसेंस प्रदान किया गया 2008-09 की शेष अवधि के लिए प्रतिवादी। गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह से खोलने के लिए छूट दी गई थी से अवधि के लिए होटल सवाडिया में आई. एम. एफ. एल./बीयर ('चालू' दुकान) 2.3.2009 31.3.2009 तक।

4. उक्त लाइसेंसों के अनुदान से दुखी होकर, पहला प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि कुछ के संबंध में आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्नान घाट आदि के स्थान जैसे पहलू तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे। द्वारा की गई सिफारिशें अधिकारी अत्यधिक अनुचित और अनुचित थे; और कि छूट बेहद मनमाने तरीके से दी गई थी और इसलिए, विशेष विशेषाधिकार और लाइसेंस का अनुदान दिया गया था कुल्हाड़ी के लायक था। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया, अभिलेख से खुद को संतुष्ट करने के लिए कहा कि किस तरह से छूट की शक्ति का प्रयोग किया गया था,

और उसके बाद अभिलेख का अवलोकन और विभिन्न पर विचार करने पर सिफारिशें, यह अभिनिर्धारित करने के लिए आईं कि जहाँ तक प्रतिवादी का संबंध है नंबर 5 एक बीयर पार्लर 'ऑन' दुकान की मंजूरी के लिए चिंतित था। अनन्य अनुदान से पहले नियमों में ढील देते हुए पारित किया गया विशेषाधिकार। जहाँ तक आई. एम. एफ. एल. रेस्तरां लाइसेंस की मंजूरी की बात है छठे प्रतिवादी के सम्मान का संबंध था, उच्च न्यायालय उन्होंने इसी तरह का विचार व्यक्त किया। हम सोचते हैं कि यह पुनः उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित अंतिम निष्कर्षः

> ''13. नियम 34 का प्रावधान विशेष रूप से निर्धारित करता है कि में उल्लिखित न्यूनतम दूरी पर प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त दो में ढील देने का आदेश के बीच न्यूनतम दूरी के संबंध में खंड प्रस्तावित दुकानें और पूजा स्थल अर्थात विष्णु मंदिर, पेट्रोल पंप और बस स्टैंड, राज्य का आदेश सरकार विशेष अनुदान की मंजूरी/अनुदान को मंजूरी दे रही विरोधी पक्ष 5 और 6 के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं हो सकता है कानून में बनाए रखा।''

5. ऐसा कहने के बाद उच्च न्यायालय ने धारा 41 को संदर्भित किया बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") और निम्नलिखित रूप में देखा गयाः-नियमों

के नियम 34 में एक वैधानिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है - विभाग छूट देने के कारणों के साथ आदेश पारित करेगा प्रतिबंध। जब इस तरह का उल्लंघन हुआ हो वैधानिक कर्तव्य, उसी को धारा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है 41 अधिनियम से

6. उपरोक्त दृष्टिकोण होने के कारण, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया विशेषाधिकार और निजी के पक्ष में दिए गए लाइसेंस उसमें उत्तरदाता।

7. हमने श्री भास्कर पी. गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ को सुना है। अनुदान के लाभार्थियों के लिए सलाहकार, श्रीमती कीर्ति रेणु मिश्रा, राज्य के विद्वान वकील और श्री जी. रामकृष्ण प्रसाद, दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

8. शुरुआत में ही हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यह स्वीकृत स्थिति है कि दोनों प्रस्तावित स्थल निषिद्ध के दायरे में आते हैं नियमों के नियम 34 (1) (डी) और (ई) के तहत परिकल्पित। नियमों के नियम 34 में कहा गया है कि विक्रेता के परिसर में शराब पीने के लिए कौन से लाइसेंस हैं दिया नहीं जाना चाहिए। उक्त नियम इस प्रकार हैः

> ''34. शराब पीने की दुकानों के लिए लाइसेंस विक्रेता के परिसर को कुछ स्थानों पर अनुमति नहीं दी जाएगी
>
> : (1) उपभोग के लिए किसी भी नई दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

विक्रेता, परिसर में शराब की -

((क) किसी बाज़ार में, या

(ख) बाजार के प्रवेश द्वार पर, या

: स्नान के निकट-घाट, या

((ग) किसी स्थान से कम से कम पाँच सौ मीटर के भीतर पूजा, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से व्यक्तियों के स्थापित निवास अनुसूचित जाति और श्रमिक कॉलोनी से संबंधित मिलें और कारखाने, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन / यार्ड, बस स्टैंड, कृषि फार्म या अन्य स्थान सार्वजनिक रिसॉर्ट का, या

(ई) औद्योगिक क्षेत्र से कम से कम एक किलोमीटर के भीतर,सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं के क्षेत्र, गाँव के भीड़भाड़ वाले हिस्से मेंःबशर्ते कि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबंध खंड (घ) और (ङ) के तहत उल्लिखित छूट दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा।

(2) जहाँ तक संभव हो, एक स्थापित शराब की दुकान परिसर में शराब के सेवन के लिए लाइसेंस प्राप्त होगा ऐसी साइट पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इसके

तहत नहीं होगी उप-नियम (1) नई दुकान के स्थान के लिए अनुज्ञेय होगा।

(3) अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे क्षेत्रों में, देश स्पिरिट की दुकानों को तुरंत लगाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मुख्य सड़क के किनारे या किसी अन्य प्रमुख स्थान ऐसी स्थिति जो उनके रास्ते में प्रलोभन डालने की संभावना है''

9. उपरोक्त नियम के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को 1136 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 3 एस. सी. आर. को शक्ति प्रदान की गई है। में उल्लिखित न्यूनतम दूरी पर प्रतिबंध में ढील दें। (घ) और (ङ) न्यूनतम दूरी से संबंधित हैं। जैसाकि पहले से ही यहाँ संकेत दिया गया है कि कोई गुहा नहीं है कि प्रतिबंध में छूट से संबंधित रिकॉर्ड पर सामग्री नियम के उप-नियम (1) के खंड (डी) और (ई) के तहत निर्धारित 34 नियमों से। उच्च न्यायालय, जैसा कि विवादित आदेश से पता चलता है, ने अनुमोदन/मंजूरी के आदेश और इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस के अनुदान को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबंधों में ढील देने का कोई आदेश नहीं दिया गया प्रस्तावित के संबंध में खंड (घ) और (ङ) में उल्लिखित राज्य द्वारा उक्त नियम की

शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुकानें सरकार और किसी भी मामले में, कोई कारण नहीं बताया गया है। इस प्रकार, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने नोट शीट की सराहना की है फाइल करें और सही निष्कर्ष पर पहुंचे या नहीं।

10. उच्च न्यायालय ने, जैसा कि स्पष्ट है, पुनः प्रस्तुत किया है संयुक्त सचिव द्वारा किए गए संचार सरकार द्वारा फैक्स द्वारा ज्ञापन संख्या 1159/पूर्व। डीटी। 2.3.2009 रेस्तरां के बारे में आबकारी आयुक्त को संबोधित किया आरएएसएसओआई में मुकेश कुमार के पक्ष में दुकान का लाइसेंस होटल 'सवाडिया पैलेस' के परिसर में विश्राम ', प्लॉट नं. 1622, खाता पर वार्ड नं. 11, बारगढ़ नगरपालिका नं. 2542/362, शेष अवधि के लिए बारगढ़ जिले में 2008-09 और ज्ञापन संख्या 1161/Ex भी। दिनांकित 2.3.2009 रोपन के पक्ष में बीयर पार्लर "ऑन" दुकान लाइसेंस के संबंध में 16 बारगढ़ नगरपालिका, बारगढ़ जिले में 2008-09 की शेष अवधि। संचार जो हो चुका है मुकेश कुमार के पक्ष में लिखा गया इस प्रकार हैः -

> ''आपके पत्र संख्या 1214 का संदर्भ आमंत्रित करते हुए। 19.2.09 पर बताए गए विषय पर, मुझे यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि सरकार। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अनुदान देने के लिए प्रसन्न हैं श्री के पक्ष में आई. एम. एफ. एल. रेस्तरां "ऑन" दुकान लाइसेंस "रासोई

रेस्टॉरेंट" में मुकेश कुमार होटल "सवाडिया पैलेस" का परिसर, वार्ड संख्या 11, बारागढ़ नगरपालिका प्लॉट संख्या 1622, खाता संख्या 2542/रोपन , शेष अवधि के लिए बारागढ़ जिले में 2008-09 उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 34 में ढील देकर, 1965 और उत्पाद शुल्क, शुल्क के अनुसार एमजीक्यू का निर्धारण 2008-09 के लिए संरचना और दिशानिर्देश। उत्पाद शुल्क प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकताहै यदि मौजूदा नई "चालू" दुकान से आस-पास की आबकारी दुकानें प्रभावित होती हैं।"

जहाँ तक बीयर पार्लर के पक्ष में "चालू" दुकान के अनुदान की बात है रोपन साहू चिंतित हैं, ज्ञापन सं। 1161 / Ex. दिनांकित 2.3.2009 इस प्रकार हैः -

" आपके पत्र सं. 1380 का संदर्भ आमंत्रित करते हुए। 25.02.09 ऊपर बताए गए विषय पर, मुझे यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि सरकार।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मंजूरी दी गई है श्री रोपना के पक्ष में बीयर पार्लर "ऑन" दुकान का लाइसेंस प्लॉट नं. 1391/2260, खाता नं. 393/330 पर साहू जिले में बारगढ़ नगर पालिका का वार्ड संख्या 16

2008-09 की शेष अवधि के लिए बारगढ़ शर्त है कि जिला आबकारी अधिकारियों को रखा जाएगायदि आस-पास की मौजूदा उत्पाद शुल्क की दुकानें हैं तो वे जिम्मेदार हैं नई दुकान खोलने से प्रभावित।''

11. चूंकि कोई कारण नहीं बताया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने फाइल मंगाई। फाइल के अवलोकन पर उच्च न्यायालय ने संदर्भित किया सिफारिशें और, अंत में, राय दी कि कोई आदेश नहीं था आयुक्त-सह-सचिव, सरकार, विभाग द्वारा उक्त दुकानों के संबंध में नियम में ढील देते हुए पारित किया गया उत्पाद शुल्क से। इस मामले का जोर यह है कि क्या नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का कोई आदेश पारित किया गया है और क्या इसके कारण हैं। जैसा कि पहले संचार से पता चलता है, यह इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार ने ढील दी है नियम 34 के तहत प्रतिबंध और जहां तक दूसरे का संबंध है संचार का संबंध है, यह कहा गया है कि सरकार ने लाइसेंस के अनुदान को मंजूरी दे दी है। विद्वान। राज्य के वकील ने नोट शीट का उल्लेख इस बात पर प्रकाश डालने के लिए किया है कि आदेश परंतुक के अनुरूप पारित किए गए थे नियमों के नियम 34 (1) और उस आधार पर संचार जारी किए गए।

12. हमने अपना चिंतित ध्यान दिया है और नोट-शीट को ध्यान से पढ़ा। की अध्ययन की गई जांच पर साथ ही यह भी कि उत्पाद शुल्क आयुक्त, उड़ीसा, कटक ने प्रस्तावों की सिफारिश की थी और इसके समर्थन में उसी ने सत्रह दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। नोट शीट में है रिपोर्ट को संदर्भित किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित साइट मौजूद है

विष्णु मंदिर से 350 मीटर, पेट्रोल से 250 मीटर की दूरी परपंप, निजी बस स्टैंड से 200 मीटर और 50 मीटर सिंचाई नहर से। अनुशंसा जो भाग बनती है नोट शीट इस प्रकार हैः -

> " बरगढ़ के कलेक्टर ने पी-84/सी में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्थानीय उपभोक्ता शराब पीने की मांग करते हैंहोटल परिसर के भीतर। अवैध शराब के मामले हुए हैं पास के क्षेत्र में बुक किया गया और इसलिए, मांग हैदुकान "चालू" दुकान से अलग होती है। "ऑन" के ग्राहक दुकान को पेग सिस्टम के साथ होटल परिसर के अंदर शराब का सेवन करना पड़ता है और सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बंद" दुकानों के साथ सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्नान घाट विरोध के अनुसार पास में नहीं है। लेकिन केवल एक इसलिए, कलेक्टर ने छूट देने की सिफारिश की है उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965 के

नियम 34 की मंजूरी के लिए सरकार के हित में प्रस्ताव। राजस्व और जाँच करने के लिए अवैध शराब का व्यापार

13. ए. के. शर्मा की आपत्तियाँ और सचिव, मानव समाज, बारगढ़ पर भी विचार किया गया है। इसके बाद, संयुक्त सचिव ने इस प्रकार की सिफारिश की हैः -

" उपरोक्त परिस्थितियों में और आबकारी आयुक्त, उड़ीसा की सिफारिश, कटक, कृपया आईएमएफएल को अनुदान देने पर विचार किया जा सकता है श्री मुकेश के पक्ष में रेस्तरां "ऑन" दुकान का लाइसेंस कुमार होटल रोपान साहो वी के परिसर में "रसोई रेस्तरां" में।

" सावाडिया पैलेस वार्ड संख्या 11, बारगढ़ नगर पालिका वर्ष की शेष अवधि के लिए बारगढ़ जिले में प्लॉट संख्या 1622, खाता संख्या 2542/362 उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965 और एमजीक्यू के नियम 34 में ढील देना।2008-09 के लिए उत्पाद शुल्क, शुल्क संरचना और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित। जिला आबकारी प्रशासन हो सकता है यदि मौजूदा आस-पास की उत्पाद शुल्क की दुकानें नई "चालू" दुकान से प्रभावित होती हैं तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है।

14. सरकार के आयुक्त-सह-सचिव, सी. आई. एस. ई. विभाग ने निम्नलिखित में इसका समर्थन किया हैः

" पी. 10/एन के नोट्स बताते हैं। हमें एक मिला था श्री ए. के. शर्मा, बारगढ़ के आई. एम. एफ. एल. 'ऑफ शॉप' नंबर 4 के विशेष विशेषाधिकार धारक (P.23-22/सी) कलेक्टर, बरगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के विरुद्ध और बारगढ़ के वार्ड संख्या 11 में होटल सवाडिया पैलेस के परिसर में रसोई रेस्तरां में आई. एम. एफ. एल. 'ऑन शॉप'। द. श्री शर्मा द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई है। इस संबंध में कलेक्टर, बारगढ़ से P.34-32/C पर प्राप्त पत्र कृपया भेजें। नज़र दौड़ाइये। श्री शर्मा की आपत्तियाँ योग्यता से रहित पाया गया। से प्राप्त रिपोर्ट आबकारी आयुक्त, जिन्हें नीचे रखा गया है, भी हो सकते हैं रासोई में आई. एम. एफ. एल. 'ऑन शॉप' की मंजूरी पर विचार करें। श्री मुकेश कुमार के पक्ष में रेस्तरां होटल सवाडिया पैलेस का परिसर, वार्ड संख्या 11 बरगढ़। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और स्वीकृत

15. उड़ीसा के आबकारी पर्यटन मंत्री ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जहाँ तक दूसरी दुकान की बात है, कलेक्टर की सिफारिशों को संदर्भित

नोट शीट, च इस प्रकार पढ़ता हैः कलेक्टर, बारगढ़ ने बताया है कि दोनों पेट्रोल पंप इस तरह से स्थित हैं कि दुकानें प्रस्तावित बार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए वह नियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों में ढील देने का सुझाव दिया है 34 उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम, 1965। कलेक्टर, बरगढ़ ने यह भी बताया है कि प्रस्तावित बीयर पार्लर लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा।

सरकार को लाने के अलावा इलाके के लोगों का उपभोग करना राजस्व और बीयर की अवैध बिक्री की जाँच, जब से क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है। केवल 3 (तीन) आईएमएफएल बंद 'दुकानें, एक आई. एम. एफ. एल.' चालू 'और एक बीयर पार्लर हैं। जनसंख्या वाले पूरे नगर क्षेत्र में कार्य करना एक लाख से अधिक। इसके लिए व्यवहार्यता और संभावना है बीयर पार्लर 'ऑन' दुकान का उद्घाटन, क्योंकि अवैध बिक्री क्षेत्र में शराब का पता चला है। प्रस्तावित दुकान शराब के अवैध व्यापार की जांच करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नए बीयर पार्लर के खुलने से आस-पास के लोग प्रभावित नहीं होंगे। नगरपालिका में आई. एम. एफ. एल. की दुकानें

16. आपत्तियों को संदर्भित करने के बाद संयुक्त सचिव और आबकारी आयुक्त की सिफारिशें पारित कर दी गई हैं।नोट शीट में निम्नलिखित क्रमः

''उपरोक्त परिस्थितियों में और उत्पाद शुल्क आयुक्त, उड़ीसा, कटक की सिफारिश से बीयर को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है।''

जिला आबकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि पास के नई दुकान खुलने से मौजूदा दुकानें प्रभावित होती हैं। सरकारी आदेश कृपया प्राप्त किए जा सकते हैं बात है

17. इसके बाद, उसी और मंत्री, आबकारी और पर्यटन ने हस्ताक्षर किए हैं इसकी मंजूरी और उसके बाद फाइल को स्थानांतरित किया गया जगह। उपरोक्त आदेशों के आधार पर संचार भेजे गए हैं।

18. पूरे नोट पत्र की गहन जांच करने पर हमारे मन में कोई संकोच नहीं है कि आयुक्त-सह-सचिव कलेक्टर की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और आबकारी आयुक्त, और नोट शीट के अवलोकन पर संयुक्त सचिव ने विचार के लिए सिफारिश की थी और आबकारी और पर्यटन मंत्री द्वारा अनुमोदन। मंत्री ने कहा, संचार के लिए वापस। हम वास्तव में कारणों को समझने में विफल हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई आदेश नहीं है अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के आदेश से पहले नियमों में ढील देना। पारित किया गया। मंत्री द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद आयुक्त-सह द्वारा भेजी गई सिफारिशों का आधार सचिव जो की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था कलेक्टर और आबकारी आयुक्त, संचार संयुक्त सचिव द्वारा

बनाया गया था। नोट शीट स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तथ्यों के लिए मन के अनुप्रयोग को इंगित करता है जो संबंधित हैं प्रस्तावित स्थल से दूरी पर प्रतिबंध और मंत्री द्वारा अनुमोदन। इस संदर्भ में, हम उल्लेख कर सकते हैं

टाफकॉन प्रोजेक्ट्स (आई) (पी) लिमिटेड में निर्णय के लाभ के साथ। संघ भारत और अन्य, जिसमें उच्च न्यायालय, ध्यान देने के बाद सचिव द्वारा पारित आदेश जो, की प्रत्याशा में संबंधित मंत्री द्वारा औपचारिक अनुमोदन ने अनुमति दी थी पक्ष इसमें अपीलार्थी को "घटना" के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ेगा प्रबंधक "। इस न्यायालय ने सचिव द्वारा अनुमति देने वाले पहले के आदेश और बाद के आदेश का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि पार्टी को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है मंत्री के औपचारिक अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रारंभिक व्यवस्था करने के प्रस्ताव के साथ और इस विचार को व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय ने आने में गलती की थी मान लीजिए कि सचिव ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था उसमें अपीलार्थी को घटना प्रबंधक के रूप में मान लें। इसके बाद, न्यायालय ने इसके औचित्य को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था मंत्री द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गयाः

न्यायालय, कि फाइल मंत्री के पास लंबित थी कुछ समय और तात्कालिकता की अभिव्यक्तियों के बावजूद, मंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वे इसमें व्यस्त थे।

"12 चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मामले "। क्या उच्च है अदालत ने इस बात की अनदेखी की है कि संबंधित फाइल फिर से थी जे. एस. एंड एफ. ए. द्वारा 30.8.1999 पर मंत्री के समक्ष एक नोट जिसमें कहा गया था कि टाफकोन को नियुक्त किया गया था इवेंट मैनेजर "तीन साल के लिए। इस पर हस्ताक्षर किए गए समर्थन "फाइल लौटी" के साथ मंत्री।

13. उच्च न्यायालय ने इस हस्ताक्षर से निष्कर्ष निकाला मंत्री ने कहा कि वास्तव में उनके द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी मेसर्स की नियुक्ति। टाफकोन या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। हम सहमत नहीं हो सकते। जहाँ मंत्री ने हस्ताक्षर किए है उनकी मंजूरी के लिए उनके सामने रखे गए विभिन्न नोटों, उनके हस्ताक्षर, बिना अधिक के, का मतलब यह होना चाहिए कि उनके पास है विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को मंजूरी दी। ″

19. यह ध्यान दिया जाए कि उक्त मामले में न्यायालय ने नियम का उल्लेख किया था लेन-देन व्यवसाय नियम, 1961 जो प्रदान करता है सभी कार्य प्रभारी मंत्री के सामान्य या विशेष निर्देशों पर किए जाने के लिए।

20. इस मामले में, संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनाए गए उड़ीसा सरकार के कार्य नियमों के नियम 7 मंत्री को अपने विभाग से संबंधित मामले के संबंध में आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह का प्रभाव प्रतिनिधिमण्डल पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 2

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः -

> ''अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) के तहत किए गए कार्य नियमों के तहत किसी भी मंत्री या अधिकारी का निर्णय संविधान राष्ट्रपति का निर्णय है या क्रमशः राज्यपाल और इन अनुच्छेदों में प्रावधान नहीं है 'प्रतिनिधिमण्डल' के लिए। कहने का मतलब है, कि निर्णय लिए गए और मंत्री या अधिकारी द्वारा कार्य नियमों के तहत की गई कार्रवाई को प्रत्यायोजित कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तविक अर्थ में शक्ति, लेकिन के कार्यों के रूप में माना जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, जो हैं

परिषद की सहायता और सलाह पर उनके द्वारा लिया गया या किया गया मंत्रियों का "।

21. पीठ ने अपनी राय को मूर्त रूप देने के लिए निर्भरता रखी है यू. पी. और अन्य राज्यों के बारे में। वी. प्रधान संघ क्षेत्र समिति और Ors.3 और सातों द्वारा घोषणा-में न्यायाधीश पीठ शमशेर सिंह बनाम। पंजाब और अन्र राज्य। पूर्णता के लिए, हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 27 में क्या कहा गया हैः -

''27. दत्तात्रेय मोरेश्वर बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड ओआरएस। , 5 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि कार्यकारी निर्णय लेने और प्रमाणित करने में चूक अनुच्छेद 166 में उल्लिखित रूप में नहीं बनाता है निर्णय स्वयं अवैध है, इस आधार पर कि इसके प्रावधान थे निर्देशिका और अनिवार्य नहीं

22. इस संबंध में हम सेठी ऑटो के एक अंश को उद्धृत कर सकते हैं। सर्विस स्टेशन और एक अन्य वी। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्यः

''14. यह कहना ठीक नहीं है कि विभागीय फाइल में टिप्पणियाँ होती हैं प्रभावी आदेश के लिए कानून की मंजूरी

नहीं है। ए. एक अधिकारी द्वारा नोट करना उसके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है विषय को। यह एक अधिकारी की राय से ज्यादा कुछ नहीं है। विभाग और अंतिम निर्णय लेने के लाभ के लिए प्राधिकरण। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आंतरिक संकेतन बाहरी संपर्क के लिए नहीं हैं। फाइल में टिप्पणियाँ समाप्त होती हैं एक निष्पादन योग्य आदेश में, पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करते हुए, केवल तभी जब यह विभाग में अंतिम निर्णय लेने के अधिकार तक पहुँचता है, उसकी मंजूरी प्राप्त करता है और अंतिम आदेश होता है संबंधित व्यक्ति को सूचित किया गया।''

23. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। एम. आर. मंडल और एक अन्य यह भी माना गया है कि फाइल पर एक आदेश पारित किया गया है और नहीं संचारित कानून की नजर में अस्तित्व में नहीं है।

24. वर्तमान मामले में यह चमकदार है कि फ़ाइल में था संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव के पास गए जिन्होंने आदेश को सूचित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा नियम 34 (1) के खंड (घ) और (ङ) में निहित प्रतिबंधों में ढील देने का कोई आदेश नहीं है। के बीच न्यूनतम दूरी के संबंध में नियम प्रस्तावित दुकानें और विष्णु मंदिर, पेट्रोल पंप और बस स्थिति और निर्णय के अंतिम भाग में व्यक्त

किया गया है नियम 34 जो पारित करने के लिए विभाग पर एक वैधानिक कर्तव्य डालता है प्रतिबंधों में ढील देने के कारणों के साथ। हम विक्षिप्त हैं यह सोचने के लिए कि उच्च न्यायालय, जहाँ तक राय के पहले भाग की बात है संबंधित है, इस तथ्य से निर्देशित किया गया है कि आयुक्त-सह-सचिव ने अपनी सिफारिश में आबकारी और पर्यटन मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया था नियमों के नियम 34 (1) के खंड (डी) और (ई)। यहाँ यह बताना उचित है कि नोट शीट से यह स्पष्ट है कि सचिव ने प्राप्त प्रस्ताव का उल्लेख किया था कलेक्टर, आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया अनुमोदन, विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ और यह भी विचार व्यक्त किया कि उक्त आपत्तियाँ योग्यता से रहित थीं और तदनुसार, अनुमोदन के लिए अनुशंसित। नोट का संचयी प्रभाव शीट यह दिखाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है कि प्रत्येक प्राधिकरण दूरी के बारे में जानता था और खंडों में छूट के लिए अनुशंसित था (डी) और नियम 34 के उप-नियम (1) के (ङ) और संबंधित मंत्री उसी का समर्थन किया था। नियम या उप का उल्लेख न करना एक आदेश पारित करना। प्रमुख परीक्षण अनुप्रयोग होना चाहिए। प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना। आदेश का दूसरा भाग, यदि उचित रूप से सराहना की गई, यह बताती है कि कोई कारण नहीं है अभिलिखित। नियम 34 (1) के परंतुक में एक अभिधारणा दी गई है कि खंड (घ) और (ङ) के तहत उल्लिखित दूरी हो सकती है - विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा छूट। कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशें

संदर्भित करती हैं - परिस्थितियाँ, अर्थात्, कि उपभोग की मांग है होटल परिसर के भीतर शराब का; कि अवैध शराब के मामलों में पास के क्षेत्र में बुक किया गया है; और यह कि प्रस्ताव में है सरकारी राजस्व का ब्याज। ने कहा कि सिफारिशों, जैसा कि प्रतिबिंबित है, के साथ सहमति व्यक्त की गई है उच्च अधिकारियों द्वारा और इसलिए, इसका कोई निशान नहीं हो सकता है संदेह है कि वे विशेष परिस्थितियों का गठन करते हैं।

25. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अपीलें हैं अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार को सलाह दी जाती है, तो नियमों के नियम 34 (1) के प्रावधान के तहत शक्ति का उपयोग करना। अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए छूट के उद्देश्य से और वर्तमान और बाद के वित्तीय वर्षों के संबंध में उक्त दुकानों से संबंधित लाइसेंस। तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, पक्षकार अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे।

के. टी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गरिमा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।